हुडको
hudco
A NAVRATNA CPSE

विकसित भारत के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

निवेशकों की प्रस्तुति

और

वित्तीय वर्ष 25 की तीसरी तिमाही और 9 महीने की प्रदर्शन विशेषताएँ

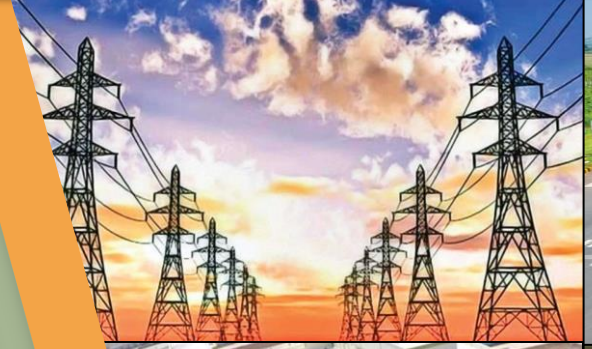

विषय-वस्तु

01

हुडको, एक अद्वितीय संस्था

02

प्रचालन प्रदर्शन

03

वित्तीय प्रदर्शन

- बॉरोइंग प्रोफ़ाइल
- परिसंपत्ति की गुणवत्ता
- प्रमुख वित्तीय विशेषताएं

04

सेक्टर आउटलुक और अवसर

हडको - एक अद्वितीय संस्था

- तकनीकी-वित्तीय संस्थान के रूप में 5 दशक से अधिक का अनुभव।
- वित्तपोषण, परामर्श और क्षमता निर्माण आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संपूर्ण परिदृश्य को समर्थन।
- राज्य सरकारों एवं उनकी एजेंसियों के साथ मजबूत संबंधों के साथ बहुक्षेत्रीय फोकस।
- भारत सरकार के प्रयासों के पूरक के लिए रणनीतिक साझेदार - पीएमएवाई 2.0 , स्मार्ट सिटी, अमृत, स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन, आदि।
- भारत सरकार के 75% स्वामित्व वाली सूचीबद्ध कंपनी।
- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एनबीएफसी-आईएफसी के रूप में पंजीकृत एक नवरत्न सीपीएसई।
- "सामाजिक न्याय के साथ लाभप्रदता" के आदर्श वाक्य के साथ लगातार लाभ कमाने वाली कंपनी

यात्रा

1970-1980

- 1970: कंपनी अधिनियम के तहत निगमन
- इक्विटी: ₹2 करोड़
- ग्रामीण आवास का वित्तपोषण
- डिजाइन एवं विकास गतिविधियाँ

1980-1990

- 1985: एचएसएमआई
- 1989: एक्सक्लूसिव अर्बन इन्फ्रा विंडो

1990-2000

- 1998: 2एमएचपी में महत्वपूर्ण भूमिका
- 1999-2000: शीर्ष 10 सार्वजनिक उपक्रमों को प्रधानमंत्री का पुरस्कार
- 1996: सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई)

2000-2010

- 2000: हुडको निवास
- 2001: अधिकृत पूंजी बढ़ाकर ₹2500 करोड़ कर दी गई 2002: अनुसूची-ए
- 2004: मिनीरत्न- I

2010-2020

- 2011-2016-कर मुक्त बांड का सार्वजनिक निर्गम
- 2015-16 क्रेडिट रेटिंग को "AAA" में अपग्रेड किया गया
- 2017: 10.19% की सार्वजनिक सूची
- लगातार 'उत्कृष्ट' MoU रेटिंग प्राप्त की

2020- अब तक

- 2023-24: सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाकर 25% की गई।
- 2023-24 - ₹830.79 करोड़ का सर्वकालिक उच्चतम लाभांश (₹4.15/शेयर)

2024-25:

- **नवरत्न का दर्जा प्राप्त**
- **एनबीएफसी-आईएफसी के रूप में पंजीकृत**
- **वित्त वर्ष 24 के लिए भारत सरकार से उत्कृष्ट समझौता ज्ञापन रेटिंग**

नवरत्न दर्जा: अप्रैल, 2024 में प्रदान किया जाएगा

- **भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए दूसरी सर्वोच्च मान्यता**

2एमएचपी – 2 मिलियन आवास कार्यक्रम
एचएसएमआई - मानव निपटान प्रबंधन संस्थान

प्रमुख विशेषताएं

पैन –इंडिया उपस्थिति, मजबूत के साथ संबंध राज्य अमेरिका

प्रमुख भूमिका में भारत सरकार की विभिन्न योजनाएँ - सभी के लिए आवास, जल जीवन मिशन आदि।

मजबूत परिसंपत्ति गुणवत्ता - सबसे कम एनपीए

मजबूत वित्तीय अनुपात - सुसंगत लाभप्रदता

उच्चतम क्रेडिट रेटिंग: घरेलू-एएए अंतर्राष्ट्रीय-संप्रभु

प्रशिक्षण और परामर्श सेवाओं सहित मूल्य वर्धित सेवाएं

'नवरत्न' सीपीएसई एवं एनबीएफसी- आईएफसी

आवास एवं अवसंरचना क्षेत्र में एक स्ट्रैटेजिक प्लेयर

360 °सतत परिसंपत्ति निर्माण के लिए साझेदारी

वित्तपोषण

- खरीदने की सामर्थ्य आवास
- आधारभूत संरचना :
  - सामाजिक इन्फ्रा - अस्पताल, सरकार भवन , जल आपूर्ति ;
  - वाणिज्यिक अवसंरचना - सड़क, राजमार्ग, शहरी गतिशीलता, बंदरगाह, ऊर्जा
- भूमि अधिग्रहण

भारत सरकार की योजनाएं

- समकक्ष अनुदान
- पीएमएवाई- शहरी और ग्रामीण
- स्मार्ट सिटी
- अमृत
- स्वच्छ भारत मिशन
- जल जीवन मिशन

प्रधान मंत्री आवास योजना Pradhan Mantri Awas Yojana

SMART CITIES MISSION Smart India

अमृत Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

Har Ghar Jal Jal Jeevan Mission

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

BHARATMALA ROAD TO PROSPERITY

कंसल्टेंसी

- वास्तु
- शहरी & स्थानीय योजना
- मूल्यांकन & निगरानी
- संपत्ति मुद्रीकरण
- पर्यावरण अध्ययन

क्षमता निर्माण

- पेशेवरों का प्रशिक्षण / में - घर के कर्मचारी
- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण PROGRAM'S
- समर्थन अनुसंधान शहरी क्षेत्र में क्षेत्र.

उधार लेने वाले भागीदार: केंद्र/राज्य सरकारें, राज्य की सार्वजनिक एजेंसियां, यूएलबी और विशिष्ट संस्थाएं

पैन-इंडिया उपस्थिति

(सक्षम बनाना - व्यवसाय विविधीकरण, बढ़ी हुई ब्रांड पहचान, सरकारी पहलों का बेहतर लाभ उठाना और क्षेत्रीय गतिशीलता को अपनाना)

- **पंजीकृत कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली में।**
- **पूरे भारत में 21 क्षेत्रीय कार्यालय और 11 विकास कार्यालय।**
- **प्रशिक्षण एवं अनुसंधान शाखा – ह्यूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट (एचएसएमआई), नई दिल्ली**
- **कार्मिक संख्या (दिसंबर, 2024 तक)- 580**
  - विविध पृष्ठभूमि के अधिकारी – 498 [वित्त, इंजीनियर, वास्तुकार, टाउन प्लानर, पर्यावरणविद्, कानूनी, मानव संसाधन और आईटी]
  - महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना - 31% (180)

उच्चतम क्रेडिट रेटिंग

दीर्घावधि ऋण के लिए AAA रेटिंग

* पारंपरिक रेटिंग से दो पायदान ऊपर

अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग संप्रभु रेटिंग के बराबर

तिमाही3/नौमाही वित्तीय-वर्ष पर शेयरधारकों की संभावना

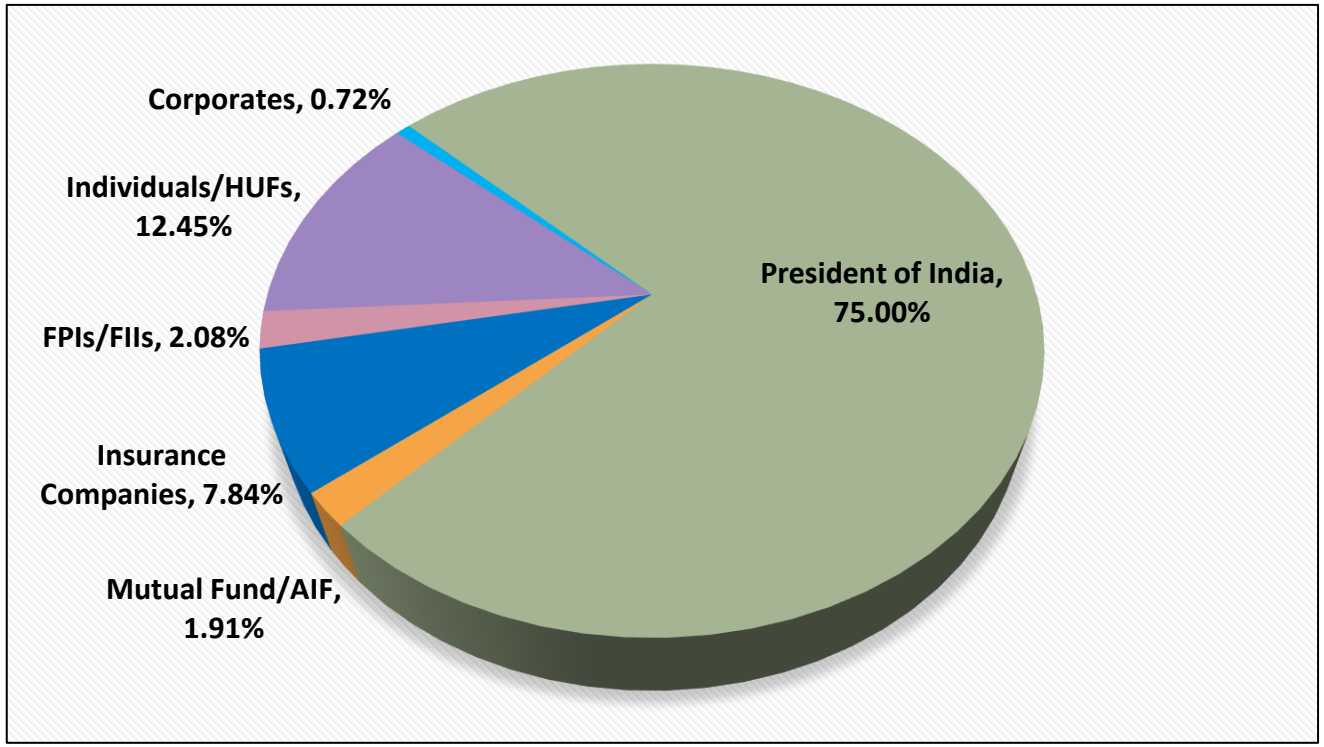

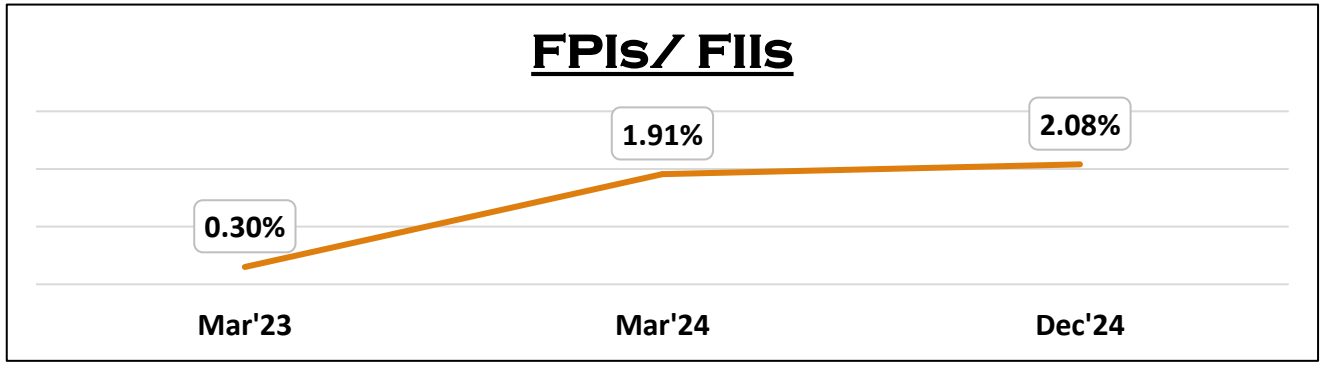

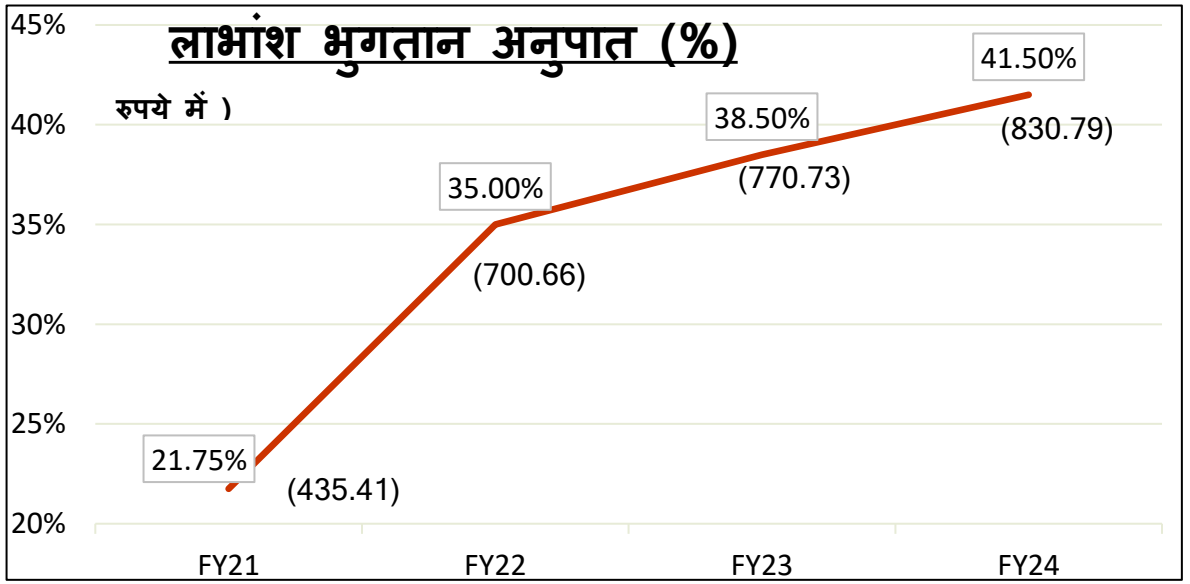

बढ़ता बाजार पूंजीकरण एवं निवेशकों का विश्वास

बाजार पूंजीकरण

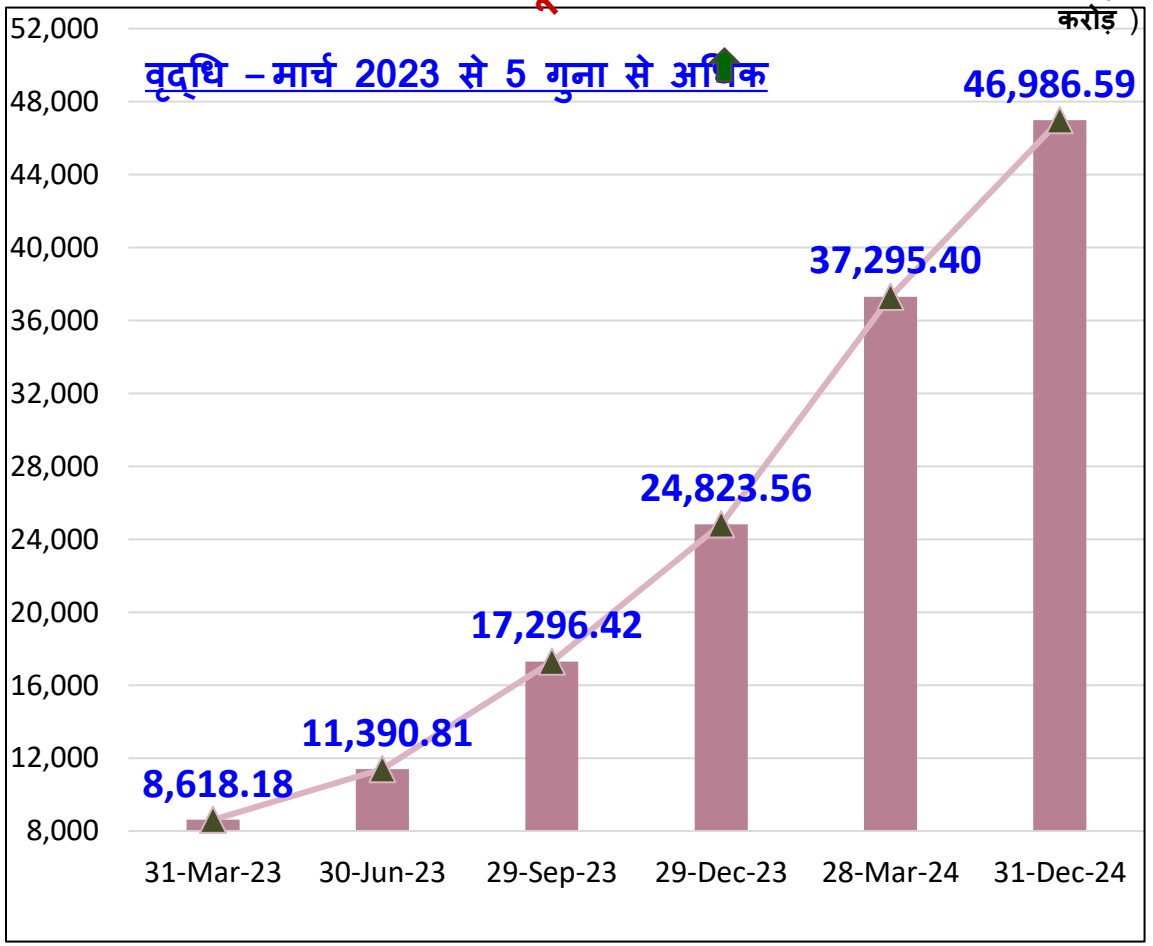

मार्केट कैप के आधार पर शीर्ष 200 कंपनियों में शामिल।

प्रति शेयर आय – ₹ 13.20 (वार्षिक)

प्रति शेयर बुक वैल्यू – ₹ 89.75

प्रचालन प्रदर्शन

- ग्रोथ ट्रेजेक्टरी
- ऋण पोर्टफोलियो
- श्रेणीवार स्वीकृति
- श्रेणीवार संवितरण

अद्वितीय ग्रोथ ट्रेजेक्टरी

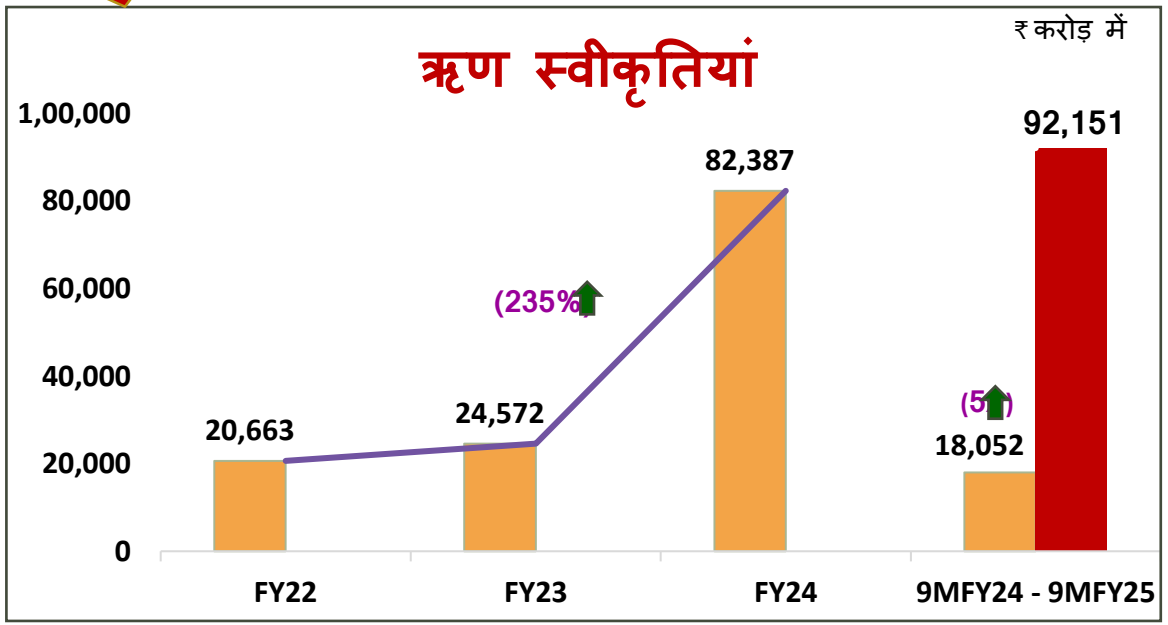

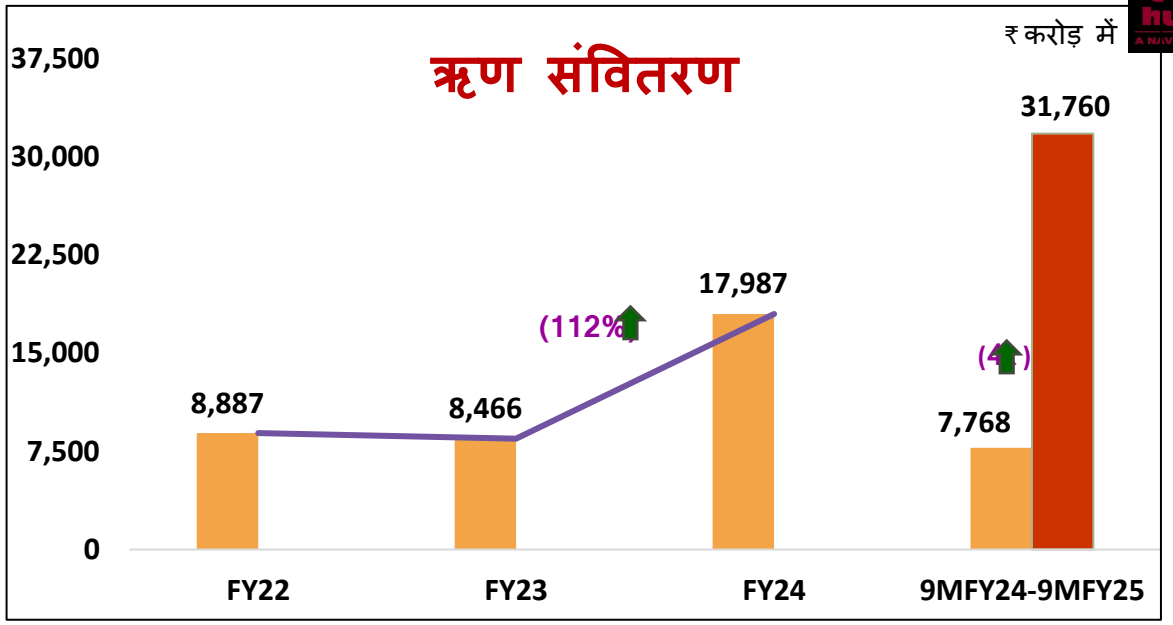

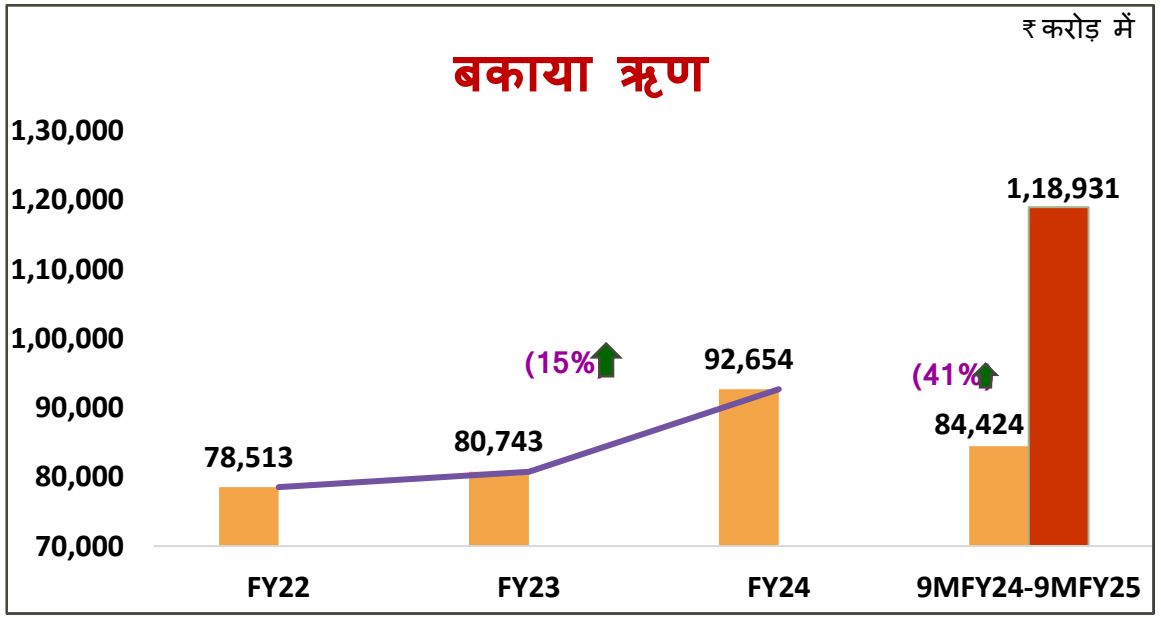

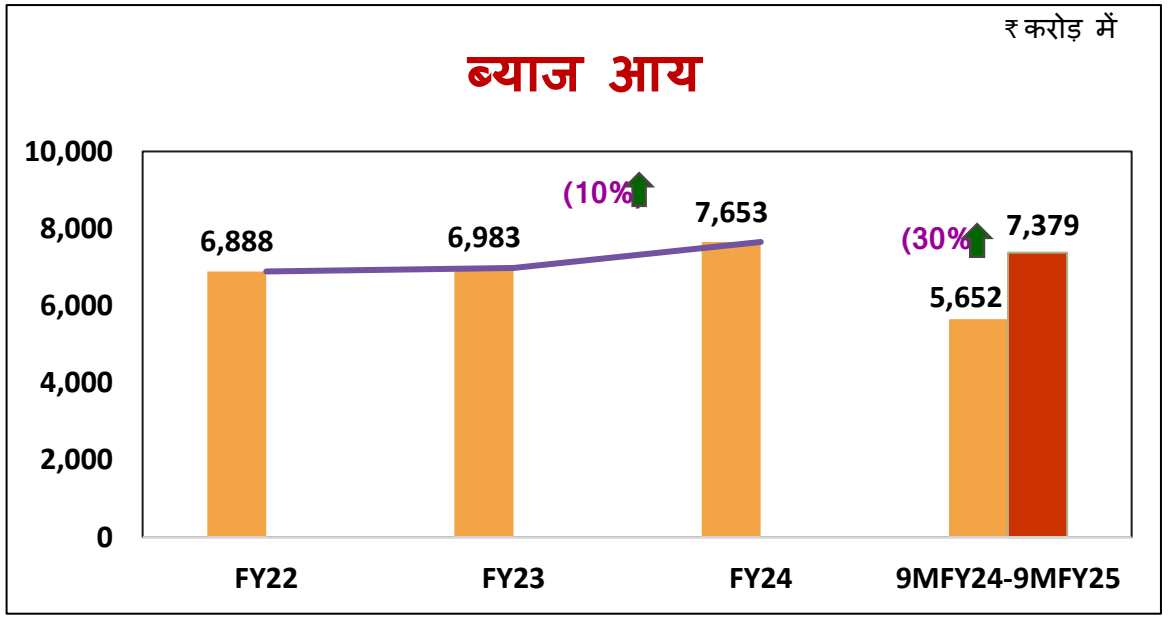

ऋण पोर्टफोलियो

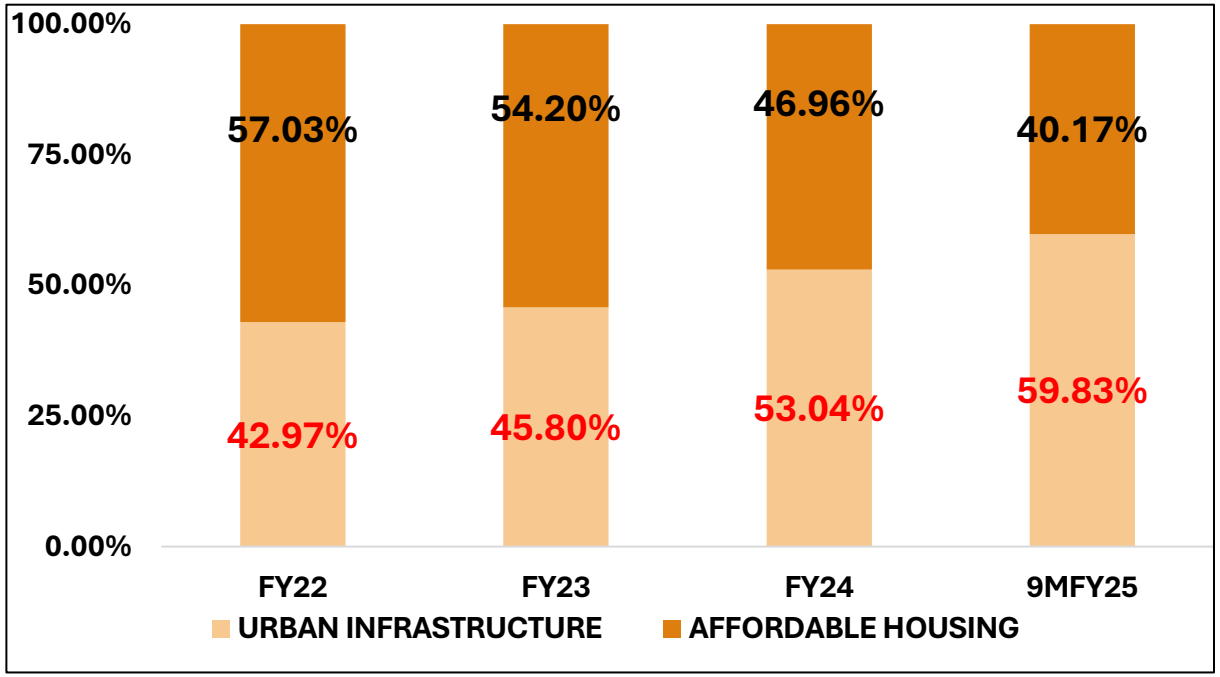

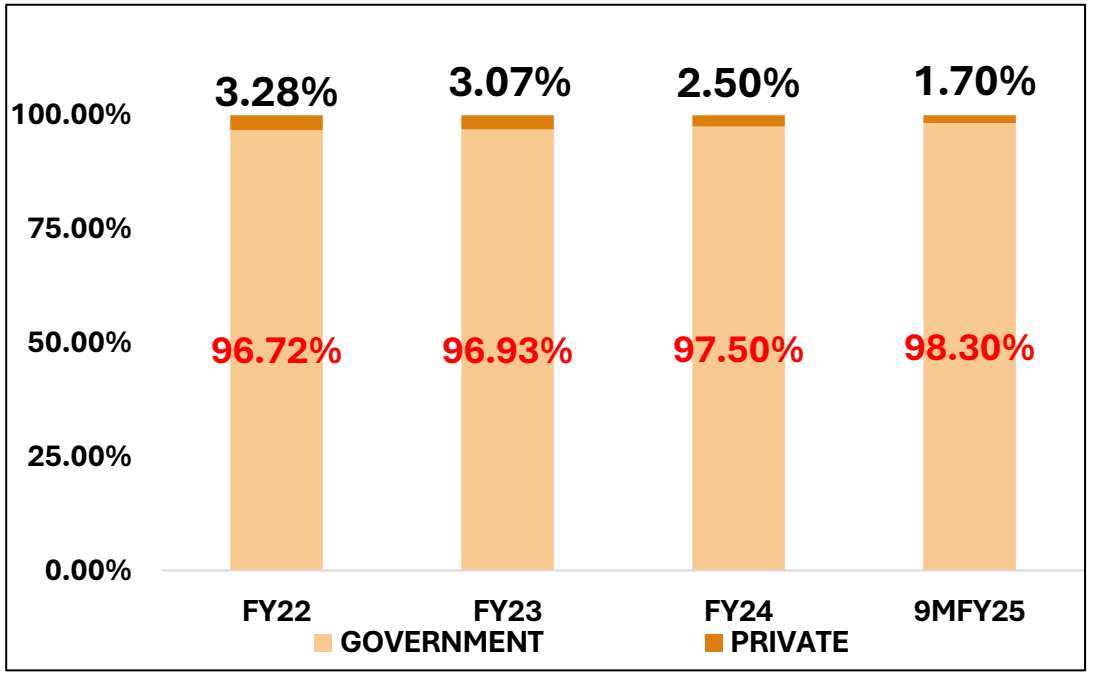

विवरण (₹ करोड़ में)	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 23	वित्त वर्ष 24	नौमाही	
				वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 25
शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर	33,735	36,982	49,143	41,308	71,153
किफायती आवास	44,778	43,761	43,511	43,116	47,778
कुल	78,513	80,743	92,654	84,424	1,18,931
सरकार	75,934	78,267	90,342	82,032	1,16,914
निजी	2,579	2,476	2,312	2,392	2,017

पीएमएवाई 2.0 के साथ किफायती आवास पोर्टफोलियो में वृद्धि होगी

ऑर्डर बुक / ऋण स्वीकृति - भविष्य की पाइपलाइन का निर्माण

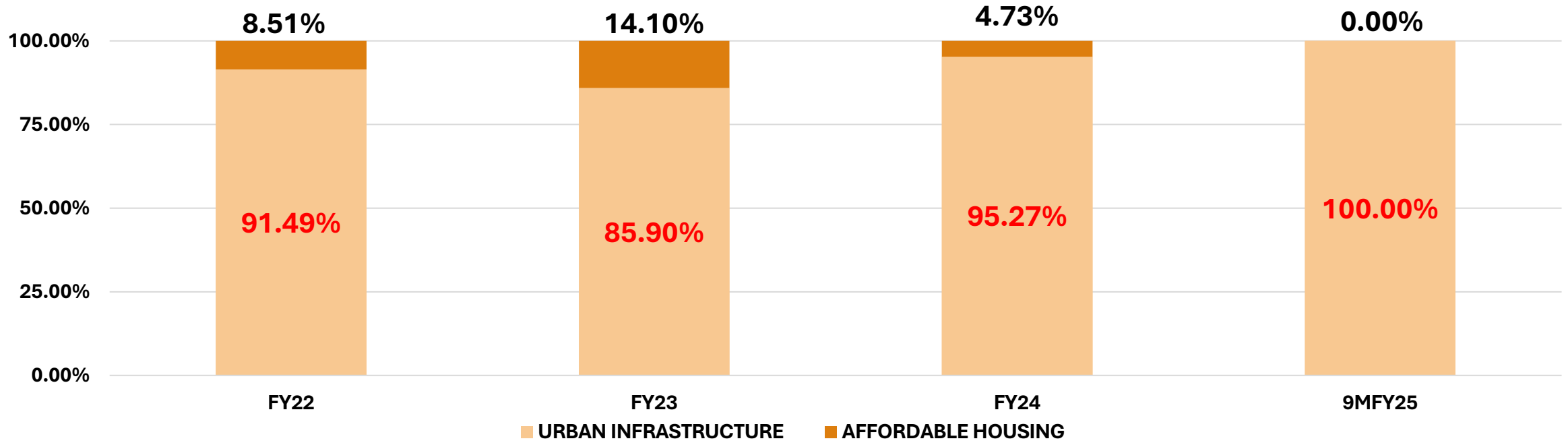

विवरण (करोड़ रुपए में)	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 23	वित्त वर्ष 24	9 एम	
				वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 25
शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर	18,904	21,106	78,488	17,283	92,151
किफायती आवास	1,759	3,466	3,899	769	-
कुल	20,663	24,572	82,387	18,052	92,151

नौमाही वित्त-वर्ष25 के दौरान अब तक के सबसे अधिक स्वीकृतियां

ऋण भुगतान

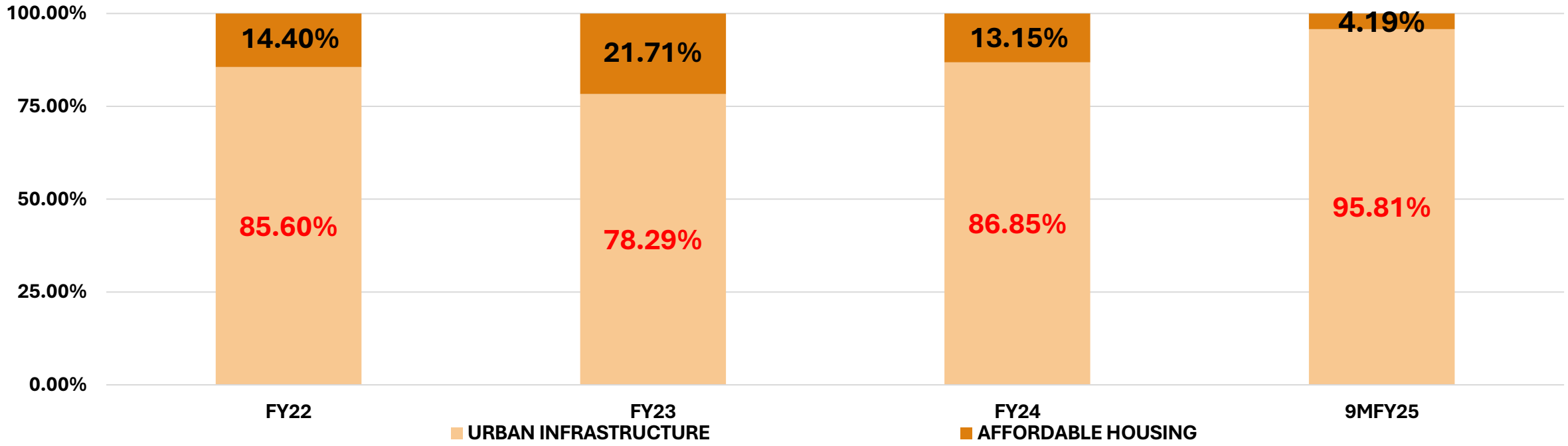

विवरण (करोड़ रुपए में)	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 23	वित्त वर्ष 24	9 एम	
				वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 25
शहरी बुनियादी ढांचा	7,607	6,628	15,621	6,633	30,428
किफायती आवास	1,280	1,838	2,366	1,135	1,332
कुल	8,887	8,466	17,987	7,768	31,760

नौमाही वित्त-वर्ष25 के दौरान अब तक का सर्वाधिक संवितरण

वित्तीय प्रदर्शन पर एक नज़र

- बॉरोइंग प्रोफ़ाइल
- परिसंपत्ति की गुणवत्ता
- प्रमुख वित्तीय विशेषताएं

उधार लेने का प्रोफ़ाइल

विवरण	9 माह-वित्त वर्ष 25	उधार की औसत लागत	9 माह-वित्त वर्ष 24	उधार की औसत लागत
A. भारत सरकार के पूर्णतः सेवा बांड	20,000.00	8.47%	20,000.00	8.47%
बी. अन्य				
कर मुक्त बांड	12,372.38	8.04%	13,382.67	8.09%
करयोग्य बांड	16,826.00	7.01%	10,750.00	6.64%
बैंक के ऋण:				
- लघु अवधि	7,897.20	7.14%	2,782.25	7.01%
- मध्यावधि	22,725.81	7.49%	16,564.18	7.52%
विदेशी मुद्रा ऋण				
- एफसीएनआर(बी)	12,212.83	5.97%	1,498.32	5.89%
- ईसीबी/ओडीए	5,361.49	5.54%	71.42	8.21%
एनएचबी/अन्य वित्तीय संस्थाओं से पुनर्वित्त सहायता	3411.37	7.11%	670.18	5.03%
उप-योग (बी)	80,807.09	7.06%	45,719.02	7.36%
कुल योग (ए+बी)	1,00,807.0	7.34%	65,719.02	7.70%

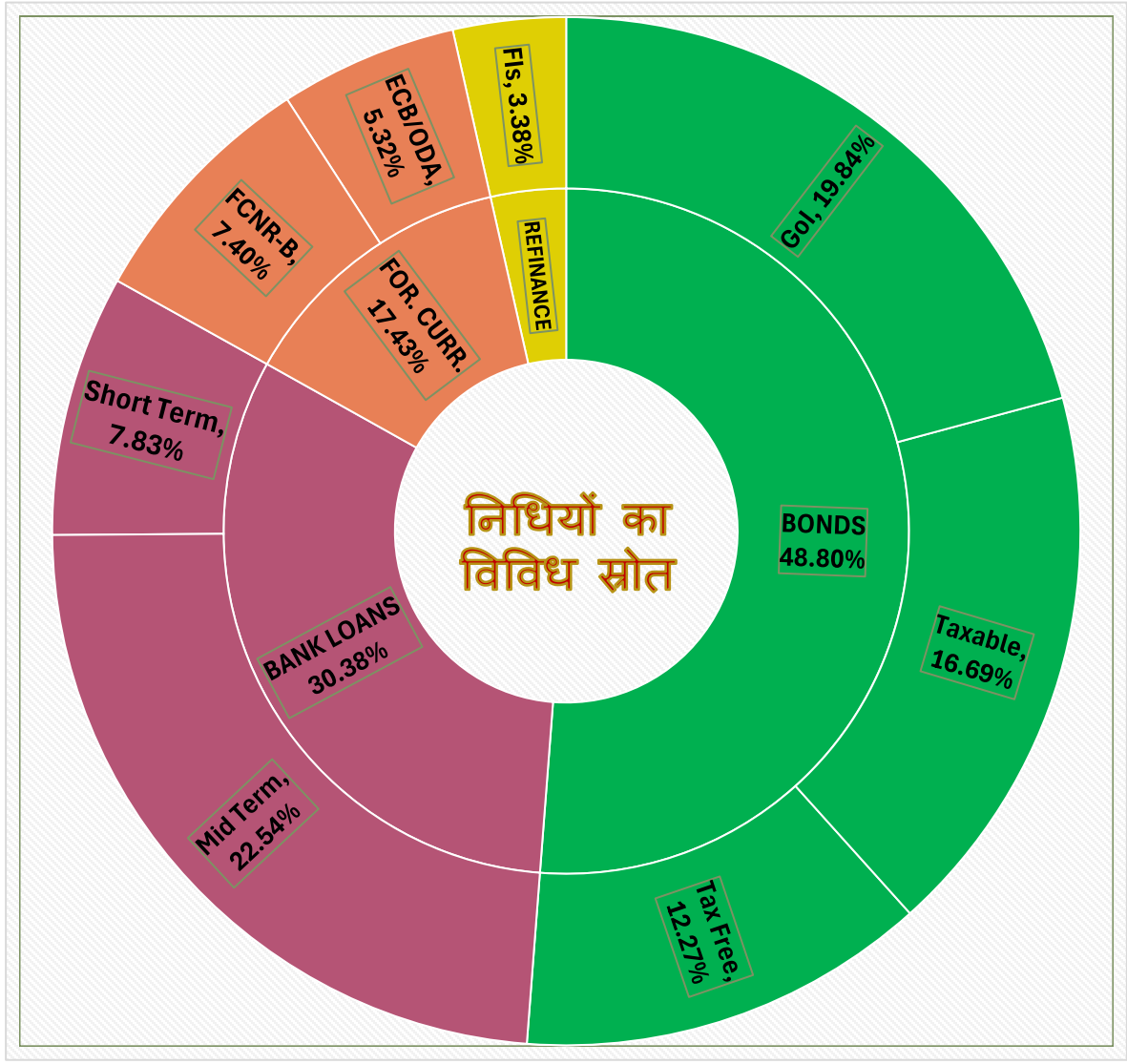

के मिश्रण के साथ वित्तपोषण के कई स्रोतों तक

बेहतर देयता प्रबंधन - मार्जिन में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ग	9 माह				12 माह			
	वित्त वर्ष 25	औसत लागत	वित्त वर्ष 24	औसत लागत	वित्त वर्ष 24	औसत लागत	वित्त वर्ष 23	औसत लागत
करयोग्य बांड	7,016.00	7.27%	1,500.00	7.48%	1,500.00	7.48%	3,970.00	7.61%
बैंक / एफआई ऋण								
- लघु अवधि	7,897.20	7.14%	2,782.25	7.01%	6,654.60	7.32%	1,769.50	6.99%
- मध्यम अवधि	9,938.00	7.61%	5,476.50	7.54%	9,002.50	7.55%	10,421.50	7.49%
- एफसीएनआर(बी)	9,720.97	5.96%	1,498.32	5.89%	3,990.18	5.96%	-	-
विदेशी मुद्रा	4,471.37	5.51%	-	-	827.85	5.29%	-	-
कुल	**39,043.54**	**6.80%**	**11,257.07**	**7.18%**	**21,975.13**	**7.10%**	**16,161.00**	**7.46%**

- **₹ जुटाए गए ₹ की तुलना में 9माह वित्त-वर्ष25 में 39,043.54 करोड़ (सर्वोत्तम) इसी वित्त वर्ष 2024 की 9वीं किस्त में 11,257.07 करोड़ रुपये**
- **कारोबार में भारी उछाल के कारण वित्त वर्ष 2025 के लिए उधार योजना ₹40,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹55,000 करोड़ की जा रही है**

लागत अनुकूलन के लिए प्रयास

- एएलएम प्रोफाइल के आधार पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के विभिन्न स्रोतों से **उधार का विवेकपूर्ण मिश्रण ।**
- एफसीएनआर(बी) ऋण 1455 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 12,213 करोड़) @5.97%।
- **अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित उपस्तिथि -** 5 वर्ष की अवधि के लिए 5.54% की दर से ¥ 94 बिलियन (₹ 5,360 करोड़) की ईसीबी उधारी ।
- **अंतर्राष्ट्रीय उधार पर निरंतर ध्यान:**
  - प्रथम बांड पेशकश के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से धन जुटाने के लिए जीएमटीएन कार्यक्रम की स्थापना
  - यूएसडी/यूरो ऋण/बांड जुटाने की संभावना सहित विभिन्न अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की खोज करना।
  - मुद्रा जोखिम से निपटने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र की स्थापना

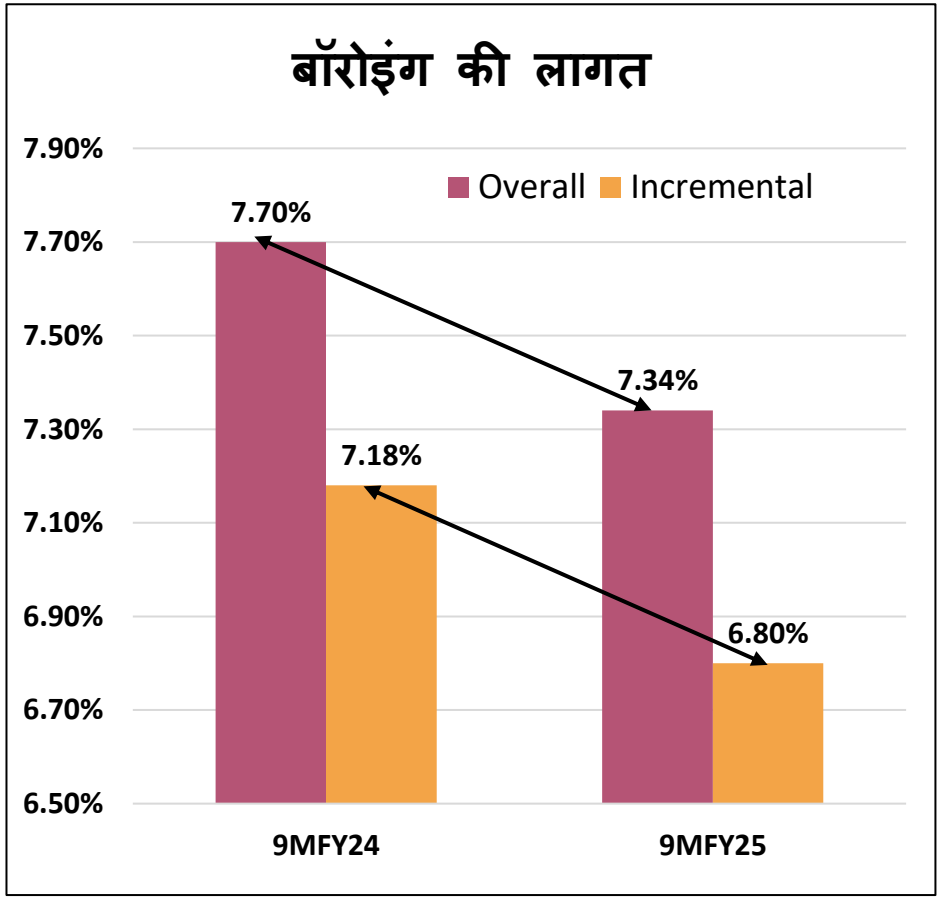

सर्वोत्तम परिसंपत्ति गुणवत्ता - एक प्रतिस्पर्धी बढ़त

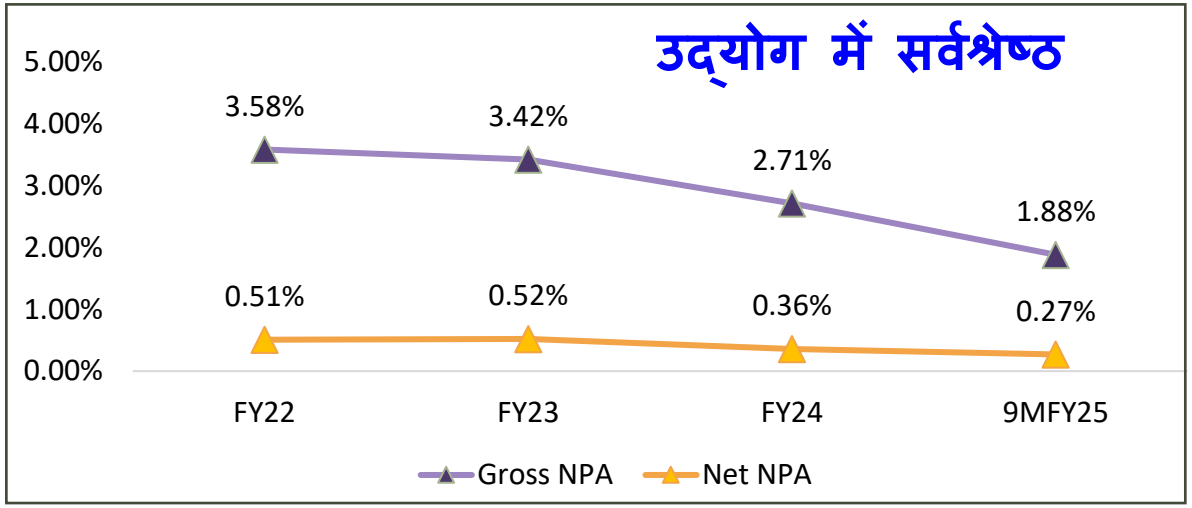

पर्याप्त प्रावधान कवरेज अनुपात (%) [1]

1. प्रावधान कवरेज अनुपात एनपीए ऋणों के विरुद्ध बनाए गए प्रावधान के अनुपात को दर्शाता है

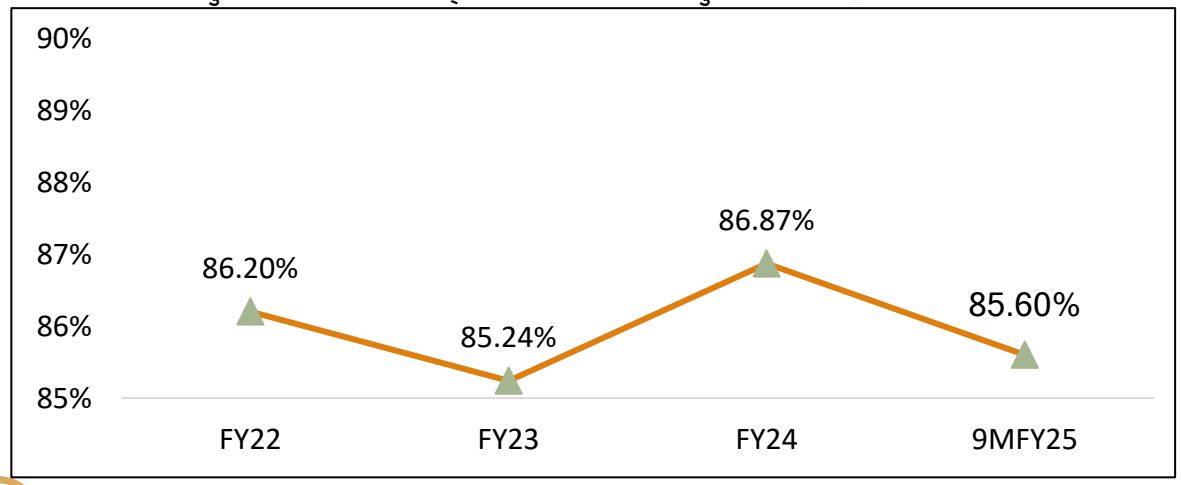

- **मजबूत मूल्यांकन और निगरानी तंत्र**
- **नीतियों और प्रक्रियाओं की आवधिक समीक्षा** - सर्वोत्तम बाजार प्रथाओं के अनुरूप
- **सरकार और उसकी एजेंसियों को ऋण** : ऋण पुस्तिका का 98.30% हिस्सा सरकार और उसकी एजेंसियों को दिए गए ऋण से बना है।
- **सरकारी गारंटीकृत ऋण** : अधिकांश ऋण राज्य सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित होते हैं।

ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां – समाधान/वसूली स्थिति

सकल एनपीए ₹ 2233.99 करोड़, शुद्ध एनपीए ₹ 321.68 करोड़, प्रावधान कवरेज 85.60%

कंसोर्टियम परियोजनाएं

- ₹1,257.10 करोड़
- 09 खातों की संख्या
- प्रावधान किया गया – 100%

एनसीएलटी समाधान के अंतर्गत कंसोर्टियम

- ₹ 1222.12 करोड़
- 06 खातों की संख्या
- प्रावधान किया गया – 100%

एनसीएलटी से बाहर (कंसोर्टियम परियोजनाएं)

- ₹34.98 करोड़
- 03 खातों की संख्या
- प्रावधान किया गया – 100%

गैर-संघीय परियोजनाएं

एनसीएलटी

- ₹29.78 करोड़
- 02 खातों की संख्या
- प्रावधान किया गया – 100%

मुकदमा दायर मामले/डीआरटी

- ₹429.75 करोड़
- शीर्ष 10: ₹ 280.12 करोड़ (65%)
- प्रावधान किया गया – 100%

- वित्त वर्ष 25 के दौरान (आज तक) 4 लंबे समय से लंबित एनपीए खातों का समाधान किया गया - ₹ 255.44 करोड़
- एनपीए खातों से 456.05 करोड़ रुपये की वसूली की गई है, जिसमें 6 सरकारी एजेंसियों से 168.77 करोड़ रुपये की वसूली भी शामिल है।

प्रमुख वित्तीय विशेषताएं

	विवरण	9एमएफवाई 25	9एमएफवाई24	% परिवर्तन - वर्ष दर वर्ष	वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 23	% परिवर्तन-वर्ष-दर-वर्ष
							(करोड़ में)
ए	**अब तक की सर्वोच्च उपलब्धियां:**						
1	ऋण स्वीकृति	92,151	18,052	5 गुना वृद्धि	82,387	24,572	235% तक की वृद्धि
2	ऋण संवितरण	31,760	7,768	4 गुना वृद्धि	17,987	8,466	112% तक की वृद्धि
3	कर पश्चात लाभ (पीएटी)	1,981.40	1,416.58	40% तक की बढ़ोतरी	2,116.74	1,701.62	24% तक की वृद्धि
4	प्रचालन से राजस्व	7,466.30	5,719.07	30% तक की वृद्धि	7,784.29	7,049.46	10.42% की बढ़ोतरी
बी	**सभी मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार:**						
5	ऋण पुस्तिका	1,18,931	84,424	41% की वृद्धि	92,654	80,743	15%
6	निवल मूल्य	17,965.59	16,247.54	11% की वृद्धि	16,614	15,445	7.60% की वृद्धि
7	ईपीएस	9.90	7.08	40% तक की बढ़ोतरी	10.57	8.50	24% तक की वृद्धि
8	बाज़ार आकार।	46,986.59	24,823.56	लगभग 2 बार	37,295	8,618	4.30 गुना
9	लाभांश (%)	14.71	11.62	3.09% तक	12.74	11.02	1.72% तक
10	संपत्ति पर वापसी (%)	2.45	2.26	0.19% तक	2.42	2.13	0.29% तक
11	सकल एनपीए (%)	1.88	3.36	1.48% तक	2.71%	3.42%	0.71% तक
12	शुद्ध एनपीए (%)	0.27	0.49	0.22% तक	0.36%	0.52%	0.16% तक

लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	Q3		9 M		12 महीने
	वित्त वर्ष 25 (समीक्षित)	वित्त वर्ष 24 (समीक्षित)	वित्त वर्ष 25 (समीक्षित)	वित्त वर्ष 24 (समीक्षित)	वित्त वर्ष 24 (लेखापरीक्षित)
आय:					
- प्रचालन से राजस्व	2.760.23	2,012.66	7,466.30	5,719.07	7,784.29
- अन्य आय	9.91	10.28	27.17	34.99	163.81
कुल आय (1)	2,770.14	2,022.94	7,493.47	5,754.06	7,948.10
खर्च:					
- वित्तीय लागत	1,762.83	1,314.21	4,888.68	3,723.26	4,963.94
- अन्य लागत	92.49	71.65	257.07	240.35	348.81
- वित्तीय साधनों की क्षति	(16.84)	(59.01)	(268.68)	(109.87)	(208.09)
कुल व्यय (2)	1,838.48	1,326.85	4,877.07	3,853.74	5,104.66
कर पूर्व लाभ {3= (1-2)}	931.66	696.09	2,616.40	1,900.32	2,843.44
कर व्यय (4)	196.63	176.90	635.00	483.74	726.70
कर पश्चात शुद्ध लाभ {5 = (3-4)}	735.03	519.19	1,981.40	1,416.58	2,116.74

मुख्य बिंदु

विवरण	9एम2025		9एम2024		वित्त वर्ष 24	
	ईबीआर सहित	ईबीआर को छोड़कर	ईबीआर सहित	ईबीआर को छोड़कर	ईबीआर सहित	ईबीआर को छोड़कर
ऋण पोर्टफोलियो (₹ करोड़)	1,18,931	98,931	84,424	64424	92,654	72,654
ऋण पर प्रतिफल (%)	9.43	9.56	9.36	9.53	9.04	9.09
कोष की लागत (%)	7.46	7.16	7.72	7.39	7.25	6.75
ब्याज प्रसार (%)	1.97	2.41	1.64	2.14	1.79	2.34
शुद्ध ब्याज मार्जिन (%)	3.19	3.85	3.20	4.12	3.18	4.04

विवरण	9एम2025	9एम2024	वित्त वर्ष 24
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	1.54	1.51	1.57
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना)	5.17	3.87	4.05
परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (%) (वार्षिकीकृत)	2.45	2.26	2.42
इक्विटी पर रिटर्न (%) (वार्षिक)	14.71	11.62	12.74
नेट वर्थ (₹ करोड़)	17,965.59	16,247.54	16,614.30
औसत नेटवर्थ (₹ करोड़)	17,289.95	15,985.97	16,029.78
प्रति शेयर ₹ 10 का	89.74	81.16	82.99
प्रति शेयर आय (ईपीएस) ₹ में	9.90	7.08	10.57

1. ऋण पर प्राप्ति की गणना ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय (एनपीए मामलों के निपटान पर प्राप्त ब्याज सहित) को औसत ऋण परिसंपत्तियों से विभाजित करके की जाती है।
2. निधियों की लागत की गणना ब्याज व्यय को औसत कुल उधार से विभाजित करके की जाती है।
3. ब्याज प्रसार, ऋण पर प्राप्ति और निधियों की लागत के बीच का अंतर है।
4. शुद्ध ब्याज मार्जिन की गणना औसत ब्याज अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों द्वारा ब्याज अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों पर शुद्ध ब्याज आय के आधार पर की जाती है (वित्त वर्ष 2024 के लिए अनुपातों को उपयुक्त रूप से पुनः तैयार किया गया है)
5. ब्याज कवरेज अनुपात की गणना ब्याज और कर से पहले की कमाई को वित्त लागत से विभाजित करके की जाती है।
6. ऋण इक्विटी अनुपात की गणना कुल ऋण को इक्विटी से विभाजित करके की जाती है।
7. इक्विटी पर रिटर्न की गणना, अवधि के अंत में शेयरधारकों के फंड द्वारा अवधि के लिए कर के बाद लाभ को विभाजित करके की जाती है, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
8. औसत परिसंपत्तियों पर रिटर्न (कर के बाद) की गणना अवधि के लिए पीएटी को औसत कुल परिसंपत्तियों से विभाजित करके की जाती है।

क्षेत्र का दृष्टिकोण और अवसर

2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और विकसित भारत @ 2047

(विकसित भारत @ 2047)

भारत में अनुमानित इंफ्रास्ट्रक्चर पूंजीगत व्यय

1. **क्रिसिल ईयर बुक 2023:** लगभग **₹ 143 लाख करोड़ 2030** तक सात वित्तीय वर्षों में बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाएगा .
2. **मॉर्गन स्टेनली ने** अपनी रिपोर्ट, **"द न्यू इंडिया - इन्फ्रास्ट्रक्चर" में अगले पांच वर्षों में** 1.45 ट्रिलियन डॉलर का संचयी व्यय अनुमानित किया है ।
3. **फिक्की की रिपोर्ट एनविज़निंग इंडिया 2030 में** अनुमान लगाया गया है कि 2040 तक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी
4. **आईसीएसआई ने** ₹ 10 लाख करोड़ से अधिक के पूंजीगत व्यय की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। विकसित भारत@2047 का लक्ष्य हासिल करने के लिए 700 लाख करोड़
5. **केयर एज रिसर्च ने** वित्त वर्ष 24 से वित्त वर्ष 28 के बीच

क्षेत्रवार अनुमानित पूंजीगत व्यय

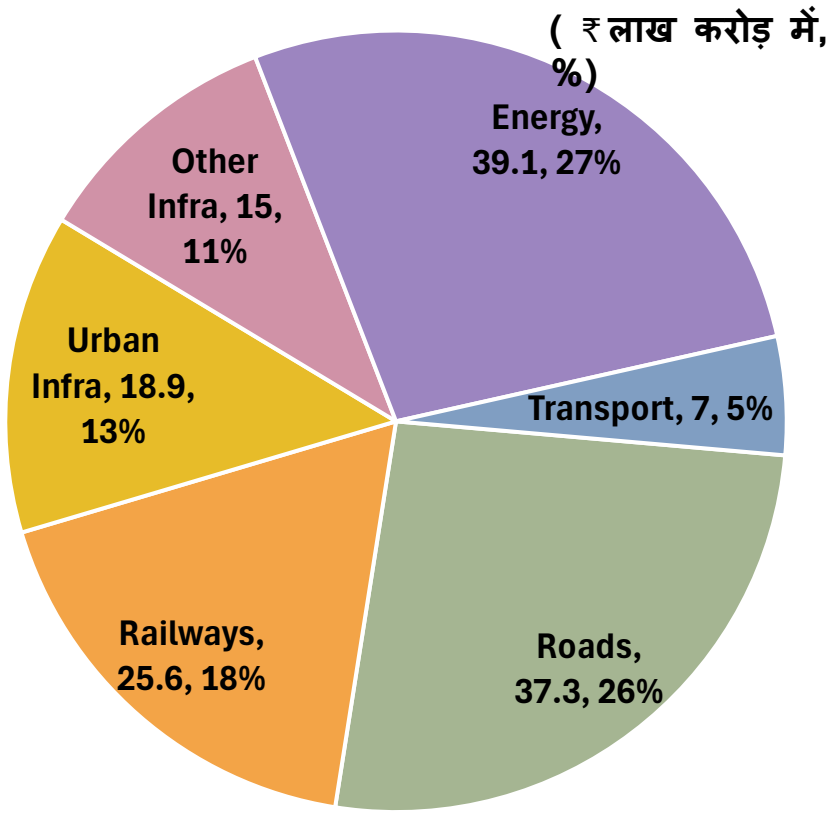

स्रोत: क्रिसिल ईयर बुक 2023

पीएमएवाई 2.0

पीएमएवाई (यू) 2.0

- शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए 1 करोड़ मकान
- कुल परिव्यय: ₹ 10 लाख करोड़
- हुडको राज्य के हिस्से के लिए प्रति-भागीय वित्तपोषण उपलब्ध कराएगा
- ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) घटक के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित

पीएमएवाई (जी) 2.0

- 2 करोड़ से अधिक मकान - 10 करोड़ व्यक्तियों को लाभ
- कुल परिव्यय: ₹ 3 लाख करोड़ (केंद्र: 2 लाख करोड़ और राज्य: 1 लाख करोड़)
- हुडको राज्य के हिस्से के लिए प्रति-भागीय वित्तपोषण उपलब्ध कराएगा

उठाए गए कदम

- एक समर्पित विभाग की स्थापना
- पीएमएवाई 2.0 के सभी वर्टिकल के लिए दिशानिर्देश तैयार करना
- बे
- राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

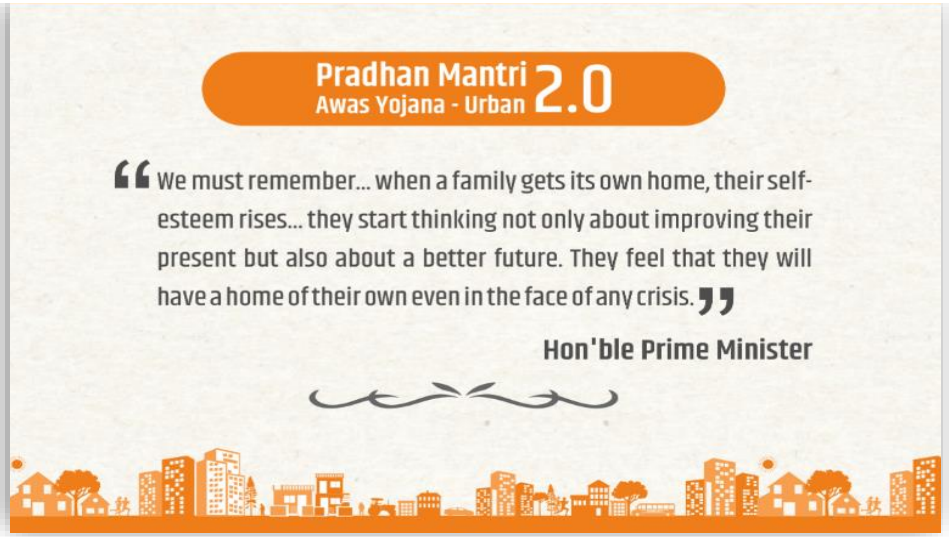

हडको से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

हडको की भूमिका – विकास के लिए प्रेरक

हुडको को हाल ही में (आरबीआई से) प्राप्त एनबीएफसी-आईएफसी का दर्जा प्राप्त होगा:

- इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए वित्त पोषण की कमी को कम करने में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करना,
- डीईए, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत अवसंरचना क्षेत्र/उप-क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करके व्यवसाय का दायरा बढ़ाया जाएगा। अवसंरचना की समन्वित सूची बनाई जाएगी।

2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित भारत (2047 तक विकसित भारत) के लिए सरकार का दृष्टिकोण निम्नलिखित पहलों के साथ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्त पोषण की भारी मांग पैदा करने के लिए तैयार है:

- भूमि अधिग्रहण
- एकीकृत टाउनशिप और औद्योगिक गलियारे
- गतिशीलता – मेट्रो, एक्सप्रेसवे आदि।
- पीएमएवाई 2.0, स्मार्ट सिटीज, अमृत, जेजेएम, एसबीएम 2.0
- स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परिवर्तन
- बंदरगाह वित्तपोषण (बंदरगाह और हवाई अड्डा)

हडको - भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की आधारशिला

आवास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए राजस्थान के साथ ₹ 1 लाख करोड़ का समझौता ज्ञापन

आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर के लिए ₹ 11,000 करोड़ का प्रस्तावित निवेश

जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए ₹10,000 करोड़।

₹4238.68 करोड़: एमएसकेवीवाई 2.0 के लिए एमएसपीजीसीएल को पीएम-कुसुम के साथ जोड़ा गया

बेंगलुरु शहर तक 8 लेन परिधीय रिंग रोड के निर्माण के लिए 27000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता

सूरत मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, गुजरात के विकास के लिए विशेषज्ञता का उपयोग करने हेतु एसआईटीसीओ के साथ समझौता ज्ञापन

विकास के लिए साझेदारी भारत 2047

बुनियादी ढांचे के सह-वित्तपोषण, पुनर्वित्तपोषण, परियोजना प्रबंधन, परामर्श और क्षमता निर्माण के लिए आईआईएफसीएल के साथ समझौता ज्ञापन।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 से अधिक हितधारकों के साथ

टिकाऊ शहरी विकास और क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन के लिए YEIDA के साथ सहयोग।

शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए डीडीए के साथ समझौता ज्ञापन

केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के कार्यान्वयन के लिए

RITES के साथ सहयोग: शहरी परिवहन, ऊर्जा और जल प्रबंधन के लिए व्यापक समर्थन।

भारत सरकार के विजन के लिए अतिरिक्त प्रयास

हडको ने अब तक का सर्वाधिक लाभांश भुगतान किया

विश्व शहरी फोरम 12, काहिरा, मिस्र

व्यवसाय उत्कृष्टता के लिए बीएमएल मुंजाल पुरस्कार

उधार की लागत को अनुकूलित करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना

ETNOW इंफ्रा फोकस अवार्ड्स 2024

MoHUA मिशन, गुवाहाटी

धन्यवाद

विकसित भारत के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण

मुख्यालय:

हडको भवन, कोर-7-ए,

इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003